

दिनांक 04.03.2015/13 फाल्गुन, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

दिल्ली पुलिस की आधुनिकीकरण योजना

994. डॉ० चंदन मित्रा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली पुलिस की आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत कुल कितनी-कितनी धनराशि आवंटित, जारी और उपयोग की गई है;

(ख) दिल्ली पुलिस द्वारा इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम के कार्यान्वयन और साइबर हाईवे का प्रयोग करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा दिल्ली पुलिस के संचार तंत्र का एक सुनियोजित और समयबद्ध रूप से आधुनिकीकरण करने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)

(क) से (ग): भारत सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिल्ली पुलिस के यातायात एवं संचार नेटवर्क के आधुनिकीकरण की योजनागत स्कीम के लिए 275.08 करोड़ रु. का अनुमोदन प्रदान किया है। इस राशि में से, दिल्ली पुलिस ने वर्ष 2012-13 में 20.34 करोड़ रु., वर्ष 2013-14 में 25.72 करोड़ तथा वर्ष 2014-15 (दिनांक 31.01.2015 तक) में 8.95 करोड़ रु. खर्च किए हैं।

11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान समझौते अनुसार में एमटीएनएल के माध्यम से लगभग 24 करोड़ रु. की लागत से 243 स्थानों पर साइबर हाईवे स्थापित किया गया है। साइबर हाईवे परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब के संबंध में, दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है कि कॉमनवेल्थ खेल 2010 के दौरान नागरिक एजेंसियों से खुदाई करने तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफबी) डालने संबंधी अनुमति समय पर प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य पूरा करने में विलंब हुआ। आवश्यक उन्नयन तथा विस्तार करने के लिए साइबर हाईवे स्कीम 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी है। इस प्रयोजन के लिए, एनसीआर/महानगरों में यातायात एवं संचार नेटवर्क तथा मॉडल यातायात प्रणाली विकसित करने के लिए 46.30 करोड़ रु. की राशि (उपर्युक्त 275.08 करोड़ रु. में से) आबंटित की गई है।

उपर्युक्त योजनागत स्कीम के अतिरिक्त, वर्ष 2006-07 से 2012-13 तक एक योजनागत स्कीम "संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम (पीएमएसयूटी) कार्यान्वित की गई थी और यह स्कीम दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त हो गई। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा इस स्कीम के तहत आबंटित और जारी/उपयोग की गई कुल राशि निम्नानुसार है:-

वर्ष	बजट आबंटन (करोड़ रु. में)	जारी/उपयोग की गई निधियां (करोड़ रु. में)
2011-12	102.40	96.78
2012-13	100.00	63.48

जब पीएमएसयूटी के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की गई, तब वित्त मंत्रालय की सलाह पर पीएमएसयूटी से भवन अवसंरचना को हटा दिया गया तथा सभी संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 'सुरक्षित शहर परियोजना' को शामिल किया गया। 'इंटेलीजेंट ट्रैफिक सिस्टम' दिल्ली के संबंध में 'सुरक्षित शहर परियोजना' का एक घटक है। यह अभी संकल्पनात्मक स्तर पर है।

